

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा  
(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 38/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड  
दायरा दिनांक: 2.5.2017  
अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सीताराम आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी
2. शिवलाल आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी  
अकवाम निवासीगण ग्राम खलील नगर तहसील पिडावा जिला झालावाड।

...अपीलाट्स

बनाम

1. भंवरी बाई पुत्री कालू एवं नन्दू बाई पत्नी गिरधारी जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी पालखन्दा तहसील पिडावा।
2. धापू बाई पुत्री कालू एवं नन्दूबाई पत्नी रामचन्द्र जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी हेमडा तहसील पिडावा।
3. सेहन बाई पुत्री कालू एवं नन्दूबाई पत्नी रामदयाल जाति बागरी निवासी खलील नगर हाल निवासी आंवली कला तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
4. परमानन्द आत्मज जगन्नाथ जाति बागरी
5. पूरी बाई बेवा जगन्नाथ जाति बागरी
6. शिवनारायण नकल पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी
7. सीताराम नकली पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी
8. प्रेमनारायण नकल पुत्र नन्दूबाई जाति बागरी  
अकवाम निवासीगण खलील नगर तहसील पिडावा जिला झालावाड।
9. तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड।

... रेस्पोजेन्ट



उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी  
श्री मनोज कुमार चांचोदिया अभिभाषक रेस्पोजेन्ट कम-1 ता 3


निर्णय

दिनांक 5.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 44/अपील/16 बउनवान भंवरीबाई वगेरा बनाम सीताराम आदि मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

5.2.2019

- 1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार पिडावा द्वारा ग्राम खलील नगर स्थित आराजी का दिनांक 24.11.2010 को तस्दीक नामा सं० 465 से असंतुष्ट होकर भंवरीबाई वगेरा द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण नन्दूबाई के वारिसान की जांच किये बगैर सीताराम, शिवलाल व परमानन्द के नाम छद्म नाम से तस्दीक किया गया है जिसे निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.10.2016 से इन्तकाल सं० 465 दिनांक 24.11.10 को तस्दीक किया गया था में तत्समय विधिक दायद वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल में अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल जेरअपील को खारिज कर विधिक दायद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पिडावा को निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा अपील धारा 76 राज० भू राजस्व अधिनियम में न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। रेस्पो० क्रम-1 लगा० 3 द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 6 वर्ष विलम्ब से पेश की गई थी जो मियाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बगैर ही अपील को स्वीकार कर अवैधानिकता की है। रेस्पो० क्रम-1 लगायत 3 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा अपील में अपनी छोटी बहर के पुत्र बालचंद व बापूलाल के होने के तथ्य पत्रावली पर आने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाकर अवैधानिकता की है। विवादित नामा० में वर्णित आराजी के संबध में एक दावा अपीलांत द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय में प्रस्तुत करने संबधी तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी के संबध में नवीन इन्तकाल तस्दीक करने का निर्णय पारित नहीं करना चाहिये था बल्कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाकर नियमित वाद में अंतिम निर्णय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश पारित करना चाहिये था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.16 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस प्रकट किया कि ग्राम खलील नगर स्थित आराजी कित्ता 14 रकबा 32 बीघा में से 1/2 हिस्से की सहखातेदार नन्दूबाई बेवा कालू बागरी की मृत्यु उपरांत उसकी विरासत का नामा० सं० 465 अपीलांत के पक्ष में तहसीलदार पिडावा द्वारा तस्दीक किया गया। रेस्पो० क्रम-1 लगा. 3 द्वारा उक्त नामा० की अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल के संबध में विधिक दायद वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल में अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल जेरअपील को खारिज कर विधिक दायद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक करने का दि० 3.10.2016 को निर्णय पारित कर अवैधानिकता की है। विवादित आराजी के संबध में रेगूलर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में जेरकार है। अतः दावे के निर्णय तक कार्यवाही नहीं करे। रेगूलर वाद में ही पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण होगा। अन्त में अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 (2) पेज 886 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत द्वारा दावा पेश करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक सजरा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय पूर्णतया सही है। अपीलांत ने अपना हिस्सा ले लिया है विवादित आराजी में आपका लोकस स्टेण्डाई नहीं है रेस्पो० क्रम 5,6,7 अधीनस्थ न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुये है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

  
रजि. सं. नं. ४६५

- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अभिभाषक से जानकारी करने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी 4.6.2016 को होना वर्णित कर प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पों की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में अपीलांत द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है लिहाजा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित में विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पटवार मण्डल मगीसपुर द्वारा इंतकाल सं० 465 ग्राम खलील नगर की दिनांक 16.4.2016 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार तह० पिडावा द्वारा दिनांक 24.11.10 को नामान्तरकरण सं० 465 तस्दीक करते समय मृतक नन्दूबाई के वारिसान की जांच नहीं की जाने का संदेह उत्पन्न होने पर जांच कराया जाना उचित प्रकट होने पर विधिक वारिसान बावत पुनः आवश्यक जांच की जाकर यदि उक्त इन्तकाल में अनियमितता पाई जाती जो संबधित पटवारी व आईएलआर पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल को खारिज कर विधिक दायद वारिसान के नाम नवीन इन्तकाल तस्दीक करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 3.10.2016 पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का कथन है कि विवादित आराजी के संबध में वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण होगा ऐसी स्थिति में नामा० को निरस्त नहीं कर नामा० कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये। अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 (2) पेज 886 का न्यायिक उद्धरण पेश किया गया। अधीनस्थ न्याया० द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 3.10.16 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा० सं० 465 को निरस्त नहीं किया है बल्कि उक्त नामा० के संबध में मृतक खातेदार नन्दूबाई के विधिक वारिसान को लेकर उत्पन्न हुये संदेह के परिपेक्ष्य में मृतक के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर यदि उक्त इंतकाल में अनियमितता पाई जाती है तो संबधित पटवारी/आईएलआर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इंतकाल को खारिज कर विधिक दायद वारिसान के नाम नवीन इंतकाल तस्दीक करने का आदेश पारित किया है। फलत् इस स्टेज पर विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना नहीं पाते हैं। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।
- 7 निर्णय आज दिनांक 5.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )  
अति० संभागीय आयुक्त  
राज्य कोटा